



मैनुअल-4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रिया कलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन निम्नलिखित मानकों/नियमों के आधार पर किया जाता है -

- 1:- उत्तरांचल(उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) की धाराओं/उपधाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करना ।
- 2:- देहरादून विकास क्षेत्र हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2001 एवं संसोधन 2003, 2007 के अनुसार कार्यवाही करना ।
- 3:- मसूरी विकास क्षेत्र हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1985 एवं ष्वासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करना ।
- 4:- देहरादून महायोजना 1982-2001 के आधार पर क्रियान्वयन ।
- 5:- ष्मन उपविधि-1998 एवं संसोधन-2003 के अनुसार कार्यवाही करना ।
- 6:- ष्वासन द्वारा जारी आवासीय योजना हेतु सम्पत्ति पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली के अनुसार कार्यवाही करना ।
- 7:- ष्वासन द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत देहरादून एवं मसूरी विकास क्षेत्र में विकास कार्य करना ।
- 8:- ष्वासन द्वारा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समय-2 पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही एवं अनुमोदित बजट के अनुसार कार्यवाही करना ।
- 9:- उत्तराखण्ड (उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) के प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण करने हेतु प्राधिकरण से नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है । निर्माण उपविधि,संरचना की स्थिरता और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपनियमों का उल्लंघन निहित न होने पर निम्नलिखित के लिये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा -
 - 1:- किसी अन्य स्वामित्व के भवन की ओर खिडकी, दरवाजा या रोषनदान का खुलना निहित न होने पर उन्हें खोलना या बन्द करना ।
 - 2:- आन्तरिक संचार के दरवाजों का प्राविधान ।
 - 3:- आन्तरिक अस्थायी विभाजन ।
 - 4:- उद्यान ।
 - 5:- सफेदी करना ।
 - 6:- रंगाई ।
 - 7:- पुनः टाईल्स या छत लगाना ।
 - 8:- पुनः फर्ष लगाना ।
 - 9:- प्लास्टर करने या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत ।
 - 10:- अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़ा सनषेड का निर्माण ।
 - 11:- न्यूनतम स्थान के माप दण्डों का उल्लंघन न होने पर कमरे का पुर्नसमावेशन ।



12:- मल, नालियों, मुख्य नालियों ,पाईपों ,केबिलों या अन्य सयन्त्र के निरीक्षण या उनके नवीनीकरण तथा मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा, किन्हीं सेवाओं के क्रियान्वयन किये जाने के लिए निर्माण कार्य ।